

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष – 02 अंक – 306 बेमेतरा, गुरुवार 02 जुलाई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज – 08 मूल्य – 1 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

सैनिक को मजबूत, फुर्तीला और तकनीकी रूप से हो कुशल

नई दिल्ली। थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगर भविष्य के आकलन से पता चलता है कि अग्निवीरों को लंबे समय तक सेवा में बनाए रखने से रक्षा बलों को मदद मिल सकती है, तो इस योजना में उचित बदलावों पर विचार किया जा सकता है। जनरल द्विवेदी ने अग्निपथ योजना को मानव संसाधन में बड़ा सुधार बताया है, जिसका मकसद युवा, फिट और भविष्य के लिए तैयार सेना बनाना है। चीन के साथ संबंधों को लेकर जनरल द्विवेदी ने कहा कि गलतफहमियों को रोकने और सीमा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हर साल 1100 से ज्यादा बार बातचीत होती है। अग्निपथ योजना के तहत सेना चार साल के लिए सैनिकों को भर्ती करती है, जिसके बाद उनमें से 25 प्रतिशत को सेवा में बनाए रखा जाता है, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को दूसरी नौकरियां करने के लिए सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों में अग्निवीरों के लिए कई पद आरक्षित किए गए हैं

मटन-दही खाने से महिला की मौत, पति की हालत गंभीर

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक बेहद हैरान और डरा देने वाला मामला सामने आया है। यहां मटन के साथ दही खाने से महिला की मौत हो गई। जबकि पति की हालत गंभीर है। जैसे ही खबर फैली इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग इस बात को लेकर सहमे हुए हैं कि क्या वाकई मटन-दही खाने से मौत हो सकती है। दरअसल ये पूरा मामला नासिक के बागलान तालुका के आखतवाड़े गांव का है। रविवार रात बुजुर्ग किसान शांताराम (78 वर्ष) और उनकी पत्नी द्वारकाबाई (68 वर्ष) ने बड़े शौक से घर पर मटन बनाया था। मटन बनने के बाद दोनों ने साथ में दही भी खाया था। खाना खाने के बाद दोनों सोने चले गए। कुछ देर बाद दोनों को उल्टी, दस्त और पेट में तेज दर्द की शिकायत होने लगी। हालत बिगड़ती देख परिजन उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला द्वारकाबाई ने दम तोड़ दिया। वहीं शांताराम की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। उन्हें मालेगांव के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर/कडी निगरानी पर रखा गया है

महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 10 तक मराठी भाषा अनिवार्य

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सभी शिक्षा बोर्डों से संबद्ध स्कूलों में पहली से दसवीं कक्षा तक मराठी भाषा पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार मराठी भाषा के संरक्षण, प्रचार-प्रसार और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. विधानसभा में घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों और अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. सरकार ने साफ किया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा.

सिलेंडर के बाद तेल के भी दाम घटे,जुलाई के पहले दिन बड़ी राहत

गैस सिलेंडर के बाद-पेट्रोल 5 और डीजल 3 रूपया सस्ता हुआ

नई दिल्ली/ एजेंसी

जुलाई महीने का पहला दिन लोगों के लिए खुशखबरी और राहत देने वाला रहा। एलपीजी गैस सिलेंडर के बाद पेट्रोल-डीजल भी सस्ता हो गया है। पेट्रोल ७5 और डीजल ७3 सस्ता हुआ है। ये कटौती नयारा एनजी ने की है। प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी नयारा एनजी ने पेट्रोल 5 रूपए प्रति लीटर और डीजल 3 रूपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। नई कीमतें आज यानी 1 जुलाई से लागू हो गई हैं। नयारा एनजी के बाद इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम भी तेल के दाम सस्ता कर सकता है। बता दें कि इससे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की

है। ऑयल कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 180 रुपये की कटौती की है। नयारा के देशभर में 7000 हजार से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। रूस की रोसनेफ्ट समर्थित फ्यूल कंपनी है। इसके साथ ही ये प्राइवेट सेक्टर की देश की सबसे बड़ी पेट्रोल-डीजल रिटेल सेलर के रूप में उभरी है। कंपनी ने अब अपने देशव्यापी नेटवर्क पर पेट्रोल प्राइस में 5 रुपये और डीजल प्राइस में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती का तोहफा दिया है। फ्लिहाल सरकारी फ्यूल रिटेलर्स ने पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दाम में कोई



कमी नहीं की है। हालांकि नयारा एनजी की तरफ से दाम सस्ता करने के बाद सरकारी तेल कंपनियां भी पेट्रोल-डीजल के दाम में कमी कर सकती है। इधर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की है। ऑयल कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के

दाम में 180 रुपये की कटौती की है। नये रेट्स की बात करें, तो दिल्ली में 3,113 रुपये का मिलने वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब सस्ता होकर 2,930 रुपये का रह गया है। इस हिसाब से गैस सिलेंडर की कीमत 183 रुपये घटाई गई है। जबकि कोलकाता में सिलेंडर अब 3,081.50

रुपए में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 3,255.50 रुपए थी। वहीं लखनऊ में कीमत 3,236 रुपए से घटकर 3,052.50 रुपए और पटना में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3,227 रुपए हो गई है। इधर 1 जुलाई से सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 4 रुपए प्रति लीटर कर दी है। पहले यह ड्यूटी 1.5 रुपए प्रति लीटर थी। समयऔर कैलेंडर अब पेट्रोल पंपों पर एक गाड़ी में एक दिन में सिर्फ 200 लीटर डीजल भरने की सीमा खत्म हो गई है, यानी अब आप अपनी गाड़ी में जितना चाहें उतना डीजल भरवा सकेंगे। इसके साथ ही फैक्ट्रियों और कॉमर्शियल खरीदारों पर लगी रोक भी हटा दी गई है।

सरकारी कंपनियों के कीमत स्थिर...

ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच जहां एक तरह नयारा एनजी ने लोगों का राहत दी है, वहीं, सरकार तेल कंपनियों के कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फ्लिहाल कीमतें स्थिर रखी हैं। ये तीनों कंपनियां भारत के एक लाख से ज्यादा पेट्रोल-पंपों में से 90 प्रतिशत से ज्यादा का फ्यूल स्टेशनों को चलाती हैं, जहां कीमतें पहले की तरह स्थिर हैं। राजधानी दिल्ली में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आउटलेट्स पर पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है।

क्या है तमिलनाडु का गोवध से जुड़ा मामला?

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम पहुंची विजय सरकार....

नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। दरअसल, इस फैसले में राज्य में गांवों और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अपनी याचिका में, तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक/ पुलिस बल प्रमुख को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि राज्य भर में बकरीद की पूर्व संख्या पर 28 मई को या किसी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े का वध न हो। उच्च न्यायालय का आदेश 1976 के



एक आदेश पर आधारित था, जिसमें दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के हित में गावों के वध पर प्रतिबंध लगाया गया था। अपनी याचिका में राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 के विपरीत बताया।

अमेरिकी राष्ट्रपति का आदेश रद्द किया

यूएस बर्थराइट सिटीजनशिप कानून बरकरार-सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली/ एजेंसी

यूएस 'बर्थराइट सिटी जनशिप' यानी जन्मजात नागरिकता कानून पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ऐसे बच्चों को जन्म से नागरिकता देने से इनकार किया गया था। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा जन्म से अमेरिकी नागरिक होगा, चाहे उसके माता-पिता देश में अवैध रूप से रह रहे हों या फिर

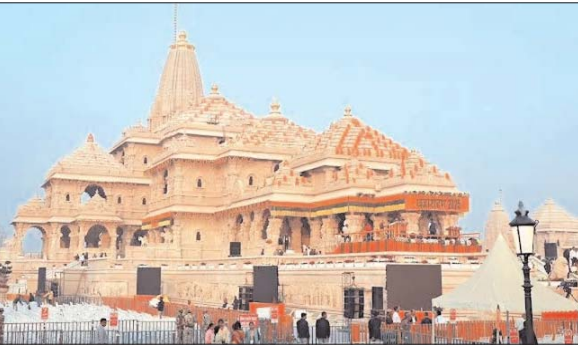


अस्थायी वीजा पर आए हों। यह फैसला दुनिया भर से अमेरिका जाकर बसने वाले लाखों प्रवासियों, खासकर भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए राहत वाली खबर है। बता दें कि अमेरिका में पिछले 158 साल से

यह व्यवस्था लागू है कि वहां जन्म लेने वाला हर बच्चा अपने जन्म के साथ ही अमेरिकी नागरिक बन जाता है। यह अधिकार अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में अमेरिका में बढ़ रहे प्रवासियों की संख्या को देखते हुए 20 जनवरी 2025 को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर बर्थ राइट सिटीजनशिप पर रोक लगा दी थी। मामला संघीय (फेडरल) जिला अदालतों तक पहुंच गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस आदेश पर संघीय (फेडरल) जिला अदालतों ने इस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी थी।

खंडवा में आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत, गांव में पसरा मातम

खंडवा। मध्यप्रदेश के खंडवा में आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में मातम छा गया है। पहली घटना खंडवा के ग्राम देवला माफी की है, जहां किसान रघुवीर पिता छगनलाल, उम्र 42 वर्ष, अपने खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। तभी अचानक बारिश होने लगी और आकाशीय बिजली गिरने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से उन्हें तत्काल मुंदी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।



में और भी खुलासे हो सकते हैं। छुट्टियांव मौसमी आयोजन सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने 7 जून को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया था. उन्होंने आरोप लगाया

कि 5 से 7.5 करोड़ रुपये की चोरी की थी. इसके बाद 8 जून सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की. 9 जून को भाजपा नेता

बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

सांसद महुआ मोइत्रा पर अंडे-पत्थरों से हमला ?

नई दिल्ली/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता जाते ही पार्टी नेताओं पर भीड़ हमला बढ़ा गया है। इस दौरान भीड़ द्वारा तुणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडे भी फेंके गए। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, कुणाल घोष जैसे नेताओं के बाद इस कड़ी में सांसद महुआ मोइत्रा का भी नाम जुड़ गया। महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स हैंडल पर भीड़ द्वारा अंडे और पत्थरों से हमला करने का एक वीडियो साझा किया है। इसमें मोइत्रा ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए



कहा कि घटना के समय राज्य पुलिस मूकदर्शक बन कर खड़ी रही। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के डीजीपी समेत कई अधिकारियों को कॉल कर चुकी हूं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। बंगाल में

सांसद के ऐसे समय पर यह घटना घटी है, जब एक दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अंडे से हमले करने की घटना पर रिपोर्ट मांगी है। महुआ मोइत्रा ने हमलावरों को भाजपा के गुंडे बताए हैं। महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स हैंडल पर हमले का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये कोई अचानक भड़के हुए लोगों का गुस्सा नहीं है। ये बीजेपी के सुनियोजित हमले हैं। बीजेपी के झंडे देखिए। महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स हैंडल पर पश्चिम बंगाल डीजीपी और बंगाल पुलिस को टैग करते हुए एक पोस्ट साझा किया।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा!

बस और ट्रक की टक्कर के बाद लगी आग,जिंदा जले 8 यात्री

नई दिल्ली/ एजेंसी

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक भीषण सड़क हादसे से हड़कंप मच गया। यहां ट्रक और बस में जोरदार टक्कर हो गई। भीषण टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 32 यात्री घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि कई और लोगों की मौत होने की संभावना जताई जा रही है। यह भीषण हादसा राजस्थान दौसा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ। कोलवा पुलिस स्टेशन इलाके में हरिद्वार से इंदौर जा रही एक बस का कंट्रोल बिगड़ गया और वह एक ट्रेलर से टकराकर आग की चपेट में आ गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल

हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही दौसा और बांंदीकुई से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया, जबकि पुलिस ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जांच चल रही है। दौसा जिले के कोलवा पुलिस स्टेशन इलाके में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बस और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में सड़क हादसा हो गया। प्रारंभिक जानकारी में एडिशनल एसपी योगेंद्र फौजदार ने बताया, इंदौर से हरिद्वार जा रही एक बस दिल्ली हाईवे पर एक रैस्ट एरिया के पास भीषण हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। एसपी और



अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बस में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। एसपी पीयूष दीक्षित ने बताया, यह हंस ट्रेवलस इंदौर की स्लीपर बस थी दूसरी

गाड़ी एक खाली ट्रक था। दोनों गाड़ियां सड़क के सीधे हिस्से पर चल रही थीं। छह लोगों की मौत जलने से हुई, जबकि दो अन्य की मौत सिर में चोट लगने से हुई। बाकी घायलों की हालत

स्थिर है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा में बस और ट्रक की टक्कर की सूचना मिलते ही कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे उन लोगों की आत्माओं को शांति दें जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और उनके परिवारों को हिम्मत दें। अब तक मिली जानकारी के अनुसार, आठ लोगों की मौत हो गई है। कई अन्य घायल हुए हैं और कई लोगों का दौसा जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, सरकार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारणों का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनानी चाहिए।

अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा पंजाब में ट्रैवलर-ट्रक भिड़त में 4 की मौत

पंजाब के बटिंडा जिले से एक दर्दनाक घटना की खबर सामने आ रही है। यह हादसा आज यानी बुधवार की सुबह हुआ है। यह घटना तब हुई जब कुछ यात्री अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहे थे। इस सड़क हादसे में चार तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए पास के एम्स में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने मीडिया से हुई बातचीत में बताया कि यह हादसा बटिंडा-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह के समय हुआ, जहां राजस्थान से अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे यात्रियों की गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई और बता दें, कि सभी श्रद्धालु एक ट्रैवलर गाड़ी में सवार थे। यह हादसा इतना भीषण था, कि ट्रैवलर गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।



संपादकीय

विवाद का यह सिलसिला केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश होते हुए यह पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया। बिहार में इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से लगभग पैंसठ लाख नाम हटाए गए।मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की कवायद को शुरू हुए एक साल पूरा हो गया है। वर्तमान में उन्नीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया जारी है। खबरों के मुताबिक, इसके जरिए अब तक करीब छह करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं। ऐसे में यह स्वाल अहम है कि क्या वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में लोग

मतदान करने के पात्र नहीं हैं? या फिर बहुत से लोग आधिकारिक दस्तावेज नहीं जुटा पाने की वजह से अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाए? सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिन लोगों के नाम सूची से बाहर किए गए हैं, उनका भविष्य क्या होगा।अगर वे मतदान के हकदार नहीं हैं, तो उनके दूसरे अधिकारों पर इसका क्या असर पड़ेगा? यह स्वाल इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार में पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनावों के बाद ऐसी खबरें आई हैं कि दोनों राज्यों में संशोधित मतदाता सूची के आंकड़ों को अब सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी

सरकारी योजनाओं में शामिल किया जाएगा। इससे यह आशंका भी गहरा रही है कि मतदाता सूची से हटाए गए लोगों को अब सरकारी योजनाओं की लाभार्थी सूची से भी बाहर किया जा सकता है।सबसे पहले बिहार में पिछले वर्ष विधानसभा चुनावों से पूर्व एसआइआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तब विपक्षी दलों ने इसके समय को लेकर स्वाल उठाए थे। उनका कहना था कि मतदाता सूची में संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग के पास पहले पर्याप्त समय था, इसके बावजूद चुनावों से ठीक पहले इस प्रक्रिया को शुरू करना उचित नहीं है। इसके बाद नागरिकता के

प्रमाण को लेकर भी यह प्रक्रिया विवादों में रही।विवाद का यह सिलसिला केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश होते हुए यह पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया। बिहार में इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से लगभग पैंसठ लाख नाम हटाए गए। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा में करीब 10.2 फीसद मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया। स्वाल यह भी है कि क्या इन लोगों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए आगे

कोई मौका दिया जाएगा, या फिर वे हमेशा के लिए मताधिकार से वंचित हो गए हैं।इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतदाता सूची का समय-समय पर संशोधन जरूरी है, ताकि जिनकी मृत्यु हो गई है या जिन्होंने फजी दस्तावेज के आधार पर अपना पंजीकरण कराया है, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएं। मगर यह चिंताजनक है कि अभी कुछ राज्यों में ही एसआइआर की प्रक्रिया पूरी हुई है और करीब छह करोड़ लोग मताधिकार से वंचित हो गए हैं, तो देश भर में ऐसे लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।सूची से बाहर किए गए लोगों

को अब अपनी नागरिकता की चिंता भी सताने लगी है, क्योंकि उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी सूची से भी बाहर होने का खतरा है। ऐसे में उनका भविष्य संकट में पड़ सकता है। यह सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि कोई पात्र व्यक्ति किसी तकनीकी कारण या समय पर दस्तावेज न जुटा पाने की वजह से मताधिकार से वंचित न रह जाए। याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र सही मायने में तभी जिंदा रहता है, जब पात्र नागरिकों के मतदान का अधिकार सुरक्षित रहे और चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न हों।

चीन देखता रह गया, हिंद महासागर में भारत ने बना ली मजबूत घेराबंदी

(नैजक कुमार दुबे)

मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच नौ महत्वपूर्ण समझौते हुए। इनमें प्रत्यर्पण संधि सबसे अधिक सामरिक महत्व रखती है। हिंद महासागर क्षेत्र लंबे समय से समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अंतरराष्ट्रीय अपराधों की चुनौती से जूझता रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेसेलस यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में केवल एक सहभागी शक्ति नहीं, बल्कि स्थिरता, सुरक्षा और विकास का सबसे भरोसेमंद केंद्र बन चुका है। सेसेलस की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के पचास वर्ष पूरे होने के अवसर पर हुई यह यात्रा सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही।

प्रधानमंत्री मोदी ने सेसेलस की संसद को संबोधित करते हुए जिस प्रकार हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाने की बात कही, वह भारत की दूरदर्शी समुद्री नीति का स्पष्ट संकेत है। भारत ने यह संदेश दिया कि हिंद महासागर केवल समुद्री व्यापार का मार्ग नहीं, बल्कि सामरिक संतुलन, आर्थिक समृद्धि और वैश्विक शक्ति संरचना का भरोसा दिया, उसने यह साबित किया कि नई दिल्ली छोटे देशों को भी बराबरी और सम्मान के साथ साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है।

इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच नौ महत्वपूर्ण समझौते हुए। इनमें प्रत्यर्पण संधि सबसे अधिक सामरिक महत्व रखती है। हिंद महासागर क्षेत्र लंबे समय से समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अंतरराष्ट्रीय अपराधों की चुनौती से जूझता रहा है। ऐसे में प्रत्यर्पण समझौता और समुद्री सुरक्षा सहयोग भारत की सुरक्षा नीति को मजबूत करने वाला कदम है। इससे भारत को पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक उपस्थिति और निगरानी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि भारत और सेसेलस की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। यही कारण है कि भारत ने सेसेलस को तेज गश्ती पोत, नौकाएं, एंबुलेंस और अन्य उपयोगी और सर्वेक्षण पोत का सेसेलस पहुंचना हिंद महासागर में भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रदर्शन भी था।

साथ ही भारत ने सेसेलस के लिए एक सो पचहतर मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर यह भी दिखाया कि उसकी विदेश नीति केवल रणनीतिक हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास आधारित साझेदारी पर आधारित है। सामाजिक आवास,

शिक्षा, परिवहन, खाद्य सुरक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भारत का सहयोग यह दर्शाता है कि नई दिल्ली अपने साझेदार देशों के विकास को अपनी प्राथमिकता मानती है। मोदी सरकार की यही नीति भारत को अन्य वैश्विक शक्तियों से अलग पहचान देती है।

इस यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल और आर्थिक सहयोग भी रहा। भारत और सेसेलस के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार, प्रत्यक्ष नौवहन संपर्क और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लेकर हुए समझौते भविष्य की आर्थिक संरचना को बदलने वाले कदम हैं। भारत की डिजिटल सार्वजनिक संरचना को सेसेलस में लागू करने की पहल यह साबित करती है कि भारत अब तकनीकी समाधान देने वाली वैश्विक शक्ति के रूप में उभर चुका है। यह मोदी सरकार की उस नीति का परिणाम है जिसमें तकनीकी को जनकल्याण और वैश्विक साझेदारी का आधार बनाया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन और छोटे द्वीपीय देशों की चुनौतियों को जिस मजबूती से उठाया, वह भी भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने साफ कहा कि जिन देशों ने जलवायु संकट पैदा नहीं किया, उन्हें उसका सबसे बड़ा बोझ नहीं उठाना चाहिए। यह बयान विकसित देशों की दोहरी नीतियों पर सीधा प्रहार भी था। भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी आधारभूत ढांचा गठबंधन और हरित ऊर्जा अभियानों के माध्यम से पहले ही विश्व मंच पर अपनी अलग पहचान बना ली है। सेसेलस द्वारा भारत की पहल में शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि विकासशील देशों के बीच भारत की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है।

साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को सेसेलस द्वारा दिया गया ब्लू होराइजन के संरक्षक सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यह सम्मान पहली बार किसी नेता को दिया गया और इससे यह संदेश गया कि हिंद महासागर क्षेत्र भारत को एक जिम्मेदार और भरोसेमंद शक्ति के रूप में देखता है। पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और समुद्री संसाधनों के संतुलित उपयोग को लेकर भारत की प्रतिबद्धता ने छोटे द्वीपीय देशों में विश्वास पैदा किया है।

सामरिक दृष्टि से देखें तो यह यात्रा चीन और सेसेलस की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। यही कारण है कि भारत ने सेसेलस को तेज गश्ती पोत, नौकाएं, एंबुलेंस और अन्य उपयोगी और सर्वेक्षण पोत का सेसेलस पहुंचना हिंद महासागर में भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रदर्शन भी था। साथ ही भारत ने सेसेलस के लिए एक सो पचहतर मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर यह भी दिखाया कि उसकी विदेश नीति केवल रणनीतिक हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास आधारित साझेदारी पर आधारित है। सामाजिक आवास,

विचार-पक्ष

पुनरीक्षण पर स्वाल, दस्तावेजों की कमी से क्या छिन गया मताधिकार?

विवाद का यह सिलसिला केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश होते हुए यह पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया। बिहार में इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से लगभग पैंसठ लाख नाम हटाए गए।मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की कवायद को शुरू हुए एक साल पूरा हो गया है। वर्तमान में उन्नीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया जारी है। खबरों के मुताबिक, इसके जरिए अब तक करीब छह करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं। ऐसे में यह स्वाल अहम है कि क्या वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में लोग

रात के एक या दो बजे का समय है । पूरे घर में अंधेरा पसरा है, सिवाय एक बेडरूम के दरवाजे के नीचे से छनकर आती मोबाइल की उस धुंधली नीली रोशनी के। आधी रात को माँ की आँख खुलती हैं। वह पानी पीने के लिए उठती है और सहज भाव से अपने बच्चे के कमरे में झाँकती है। वहाँ वो बिस्तर पे बैठा हैं-हाथ में मोबाइल है और कानों में हेडफोन मजबूती से जड़े हैं। स्क्रीन पर कुछन कुछ चल रहा है; कोई गेम पूरे जोर से चल रहा है। वक्त का होश तो जैसे पूरी तरह खो चुका है।

(**डॉ. नितिन कुलकर्णी**)

जब हम बच्चे थे, तो गर्मियों की छुट्टियों की एक अलग ही जादुई दुनिया हुआ करती थी। हम खुले आसमान के नीचे छत पर सोते थे, टिमटिमाते तारों को निहारते हुए परिवार से बतियाते थे। हम सूरज उगने से पहले उठ जाते थे, जहाँ पक्षियों की चहचहाहट और भोर की ताजी हवा एक नए उत्साह के साथ हमारा स्वागत करती थी।

रात के एक या दो बजे का समय है। पूरे घर में अंधेरा पसरा है, सिवाय एक बेडरूम के दरवाजे के नीचे से छनकर आती मोबाइल की उस धुंधली नीली रोशनी के। आधी रात को माँ की आँख खुलती हैं। वह पानी पीने के लिए उठती है और सहज भाव से अपने बच्चे के कमरे में झाँकती है।

वहाँ वो बिस्तर पे बैठा हैं-हाथ में मोबाइल है और कानों में हेडफोन मजबूती से जड़े हैं। स्क्रीन पर कुछन कुछ चल रहा है; कोई गेम पूरे जोर से चल रहा है। वक्त का होश तो जैसे पूरी तरह खो चुका है।हम अभी तक सोए नहीं? स्वाभाविक रूप से एक थका हुआ, चिंतित स्वाल हवा में तैरता है।बस मम्मा, थोड़ा सा बाकी है। अगले पाँच-दस मिनेट में पक्का सो रहा हूँ, उधर से रटा-रटाय़ा जवाब आता है।

वे दस मिनेट कब दो घंटों में बदल जाते हैं, कोई नहीं जानता। आखिरकार नौद आ ही जाती है, पर कब? इसका सटीक हिस्सा किसी के पास नहीं होता। आज देश-दुनिया के अधिकांश घरों में हर रात यही कहानी दोहराई जा रही है।

अगले दिन फिर वही चक्र चलता है- दिन के म्याहल या बारह बजे तक सोए रहना, और कई बार टोकने के बाद ही बिस्तर छोड़ना। जब वे आखिरकार उठते हैं, तो एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में कॉफी का कप होता है। शरीर तो जाग जाता है, लेकिन दिन की जो एक प्राकृतिक लय होती है, वह पूरी तरह तमोड़ चुकी होती है। रात भर जागना, दोपहर में आँखें खोलना, और भोर होने तक लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन को टक्कटकी लगाकर ताकते रहना ही अब नया नॉर्मल बन गया है।

समय बचलता है, तकनीक आगे बढ़ती है और जीवनशैली उसके अनुसार ढल जाती है। यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन मानव शरीर की बुनियादी जरूरतें नहीं बदलतीं। मानवीय जिस्म को शारीरिक आराम की दरकार होती है। मन को गहरी, सुकून भरी नींद मिलनी चाहिए। आँखों को अंधेरे की ओर दिमाग को खुद को दोबारा तरोताजा व व्यवस्थित करने के लिए शांत समय की आवश्यकता होती है।

मगर आज की पीढ़ी मानो अपने ही बायोलाॅजी से युद्ध लड़ रही है। उन्हें शायद यह मुमालता हो गया है कि ढेर सारी तकनीक और डेटा के दम पर वे इंसानी शरीर के नियमों को मात दे सकते हैं और अपनी जैविक घड़ी (बायो-रिदम) को ठेंगा दिखा सकते हैं।

जब हम बच्चे थे, तो गर्मियों की छुट्टियों की एक अलग ही जादुई दुनिया हुआ करती थी। हम खुले आसमान के नीचे छत पर सोते थे, टिमटिमाते तारों को निहारते हुए परिवार से बतियाते थे। हम सूरज उगने से पहले उठ जाते थे, जहाँ पक्षियों की चहचहाहट और भोर की ताजी हवा एक नए उत्साह के साथ हमारा स्वागत करती थी। हमारे दिन खेलने, कितानें पढ़ने, गलियों में घूमने और आपस में बातें करने में बीतते थे।

आज, कई बच्चे भूल चुके हैं कि सूर्योदय असल में कैसा दिखता है। वे सुबह की उस शांत लहर और चिड़ियों के चहकने के सीधे गवाह ही नहीं बन पाते।

चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार अफीम, हेरोइन, स्मैक, कोकीन और सिंथेटिक ड्रग्स का निरंतर सेवन व्यक्ति को मानसिक रूप से अक्षम बना सकता है। नशे का दुष्प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। इसके कारण परिवार टूटते हैं, घरेलू हिंसा बढ़ती है, बेरोजगारी और आर्थिक संकट गहराते हैं तथा अपराध और सामाजिक असुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। अनेक शोधों में यह तथ्य सामने आया है कि चोरी, हिंसा, तस्करी, यौन अपराध और संगठित अपराधों का एक बड़ा हिस्सा मादक पदार्थों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) ने वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की थीम निर्धारित की है- “विश्वव्यापी नशीली दवाओं की समस्या: स्थायी मुद्दे, नई चुनौतियाँ, अभिनव समाधान”। यह थीम इस तथ्य को रेखांकित करती है कि नशे की गिरफ्त में आए व्यक्ति को अपराधी नहीं, बल्कि सहयता और उपचार की आवश्यकता वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। समाज, परिवार,

नशे से बर्बाद होते जीवन को बचाना होगा

(ललित गर्ग)

नशीली दवाओं का दुरुपयोग मानव शरीर की लगभग प्रत्येक प्रणाली को प्रभावित करता है। हृदय, यकृत, फेफड़े, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। दीर्घकालिक सेवन व्यक्ति को अवसाद, मानसिक असंतुलन, आत्महत्या की प्रवृत्ति, स्मृति ह्रास और व्यक्तिव विघटन की ओर ले जाता है।

नशीली दवाओं का बढ़ता प्रचलन आज विश्व मानवता के सामने एक ऐसे संकट के रूप में उभर रहा है, जो केवल स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर वैश्विक प्रश्न बन चुका है। नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी लाखों लोगों के जीवन के प्रति जागरूक हो, सामूहिक प्रयासों को सशक्त बनाए और एक नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को संकल्प संख्या 42/112 के माध्यम से इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक सहयोग और कार्रवाई को मजबूत करना है। इस दिवस के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि नशीली दवाओं की समस्या का समाधान केवल दंडात्मक उपायों से नहीं, बल्कि जनजागृति, सामाजिक-पारिवारिक रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक सहयोग से संभव है।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) ने वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की थीम निर्धारित की है- “विश्वव्यापी नशीली दवाओं की समस्या: स्थायी मुद्दे, नई चुनौतियाँ, अभिनव समाधान”। यह थीम इस तथ्य को रेखांकित करती है कि नशे की गिरफ्त में आए व्यक्ति को अपराधी नहीं, बल्कि सहयता और उपचार की आवश्यकता वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। समाज, परिवार,

सरकार और स्वास्थ्य संस्थाओं के समन्वित प्रयास ही उसे पुनः सामान्य जीवन की ओर लौटा सकते हैं। विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। अनुमानतः विश्वभर में 30 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। इनमें से करोड़ों लोग नशे की लत के कारण गंभीर शारीरिक एवं मानसिक रोगों से पीड़ित हैं, लेकिन उपचार सुविधाओं तक उनकी पहुंच अत्यंत सीमित है। मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों से पीड़ित प्रत्येक आठ व्यक्तियों में से केवल एक को ही उपचार प्राप्त हो पाता है। यह स्थिति विश्व स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर चुनौती को उजागर करती है।

बीते कुछ दशकों में वैश्विक मादक पदार्थ बाजार का स्वरूप तेजी से बदला है। परंपरागत नीले पदार्थों-अफीम, हेरोइन, गांजा, चरस और कोकीन के साथ-साथ अब सिंथेटिक ड्रग्स, फेटानिल, मेथामफेटामाइन और विभिन्न रासायनिक नशीले पदार्थों का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। कृत्रिम नशीले पदार्थों के उत्पादन में कम लागत, तस्करी में कम जोखिम और अत्यधिक मुनाफे ने अवैध मादक पदार्थ उद्योग को और अधिक संगठित तथा खतरनाक बना दिया है। आज मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह आधुनिक तकनीक, डाक़ वेब, क्रिप्टोकॉरेंसी और सोशल मीडिया संस्थाओं का उपयोग कर नए उपप्लोकाओं, विशेषकर युवाओं और किशोरों, को अपना लक्ष्य बना रहे हैं। ऑनलाइन नेटवर्क और गुप्त डिजिटल लेन-देन ने नशीली दवाओं की उपलब्धता को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक आसान बना दिया है। संगठित अपराध और मादक पदार्थों का यह गठजोड़ विश्व शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है।

चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार मादक, हेरोइन, स्मैक, कोकीन और सिंथेटिक ड्रग्स का निरंतर सेवन व्यक्ति को मानसिक रूप से अक्षम बना सकता है। नशे का दुष्प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। इसके कारण परिवार टूटते हैं, घरेलू हिंसा बढ़ती है, बेरोजगारी और आर्थिक संकट गहराते हैं तथा अपराध और सामाजिक असुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। अनेक शोधों में यह तथ्य सामने आया है कि चोरी, हिंसा, तस्करी,

यौन अपराध और संगठित अपराधों का एक बड़ा हिस्सा मादक पदार्थों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।

भारत भी इस वैश्विक संकट से अछूता नहीं है। भौगोलिक स्थिति, सीमावर्ती चुनौतियाँ, बढ़ती शहरीकरण प्रक्रिया और युवाओं में बदलती जीवनशैली के कारण देश में नशीली दवाओं का दुरुपयोग चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुका है। विशेष रूप से पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा महानगरों में यह समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। भारत की पश्चिमी सीमा के निकट स्थित तथ्यांकित “गोल्डन क्रिसेंट”- अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान विश्व के प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है, जिसके कारण सीमावर्ती राज्यों में तस्करी की समस्या अधिक जटिल हो गई है। पंजाब लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की समस्या से जूझ रहा है। सीमा पार से ड्रगेन और अन्य माध्यमों से होने वाली तस्करी ने स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद की ही तरह नशे एवं ड्रग्स को व्यापक स्तर पर फैलाया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को कमजोर और सामाजिक संरचना को क्षतिग्रस्त करना है। यह केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न है। जिसके दुष्परिणाम विशेषतः पंजाब के साथ-साथ समूचे देश को भोगने को विवश होना पड़ रहा है। पंजाब नशे की अंधी गलियों में धंसता जा रहा है, सीमा पार से शुरू किए गए इस छद्म युद्ध की कीमत पंजाब की जनता को चुकानी पड़ रही है, देर आये दुरस्त आये की भाँति लगातार चुनौती बने नशीली दवाओं एवं ड्रग्स के धंधे के खिलाफ आप सरकार ने एक महत्वाकांक्षी युद्ध एवं अभियान शुरू किया है। पंजाब डेश में ड्रग्स में सर्वाधिक शल्लश उपायों में आता है। यह डेशा गतदिनों गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में “मादक पदार्थों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा” पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में सामने आया। सामाजिकविज्ञान

भारत सरकार ने नशे के विरुद्ध अनेक पहलें शुरू की हैं। ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ देश के 272 से अधिक संवेदनशील जिलों में व्यापक जनजागरण, शिक्षा और

संकुल खड़का, मधोता व कुंडगुड़ा में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन, बच्चों को बांटी पुस्तक-गणवेश

**बस्तर/मूक पत्रिका**

बस्तर विकासखंड के संकुल खड़का, मधोता और कुंडगुड़ा में बुधवार को संकुल स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप रहे। अध्यक्षता मधोता सरपंच कलावती नाग ने की।

इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सुखदेव मंडवी, शाला प्रबंध समिति अध्यक्ष चमराम यादव, बीआरसी अजय्यर कोरम, संकुल प्राचार्य श्यामलाल नेताम मंच पर उपस्थित रहे। साथ ही रैमती नाग, वासुदेव यादव, नरेश ठाकुर, संजय ठाकुर, खड़का संकुल समन्वयक कृष्णा सिंह ठाकुर, कुट्टाड़ा संकुल समन्वयक हर्देव बघेल सहित दोनों संकुलों के शिक्षक-शिक्षिकाएं, पालकगण और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन

मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्जलन से हुई। मुख्य अतिथि कश्यप ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा से ही बस्तर का भविष्य बलेगा। नियमित स्कूल आकर पढ़ाई करना और अनुशासन में रहना हर बच्चे की जिम्मेदारी है। बीआरसी कोराम ने शासन की योजनाओं की जानकारी देते हुए पालकों से बच्चों को रोज स्कूल भेजने की अपील की।

समारोह में नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर और पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। सभी बच्चों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें व गणवेश का वितरण किया गया। अतिथियों ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। शाला प्रवेश उत्सव के माध्यम से बस्तर अंचल में शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। आयोजन को लेकर बच्चों व पालकों में खासा उत्साह दिखा।

नेमंडू मत्स्य बाँज प्रक्षेत्र का
करेंगे निरीक्षण,
जनप्रतिनिधियों से
मुलाकात के साथ
आदिवासी छात्रावास-आश्रम
का भी लेंगे जायजा

बीजापुर/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ शासन के आदिम
जाति विकास, कृषि विकास एवं
जलिकान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी
महसूलपालन तथा पशुधन विकास
मंत्री रामविचार नेताम आज दो
दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंचे।
प्रवास के दौरान वे विभागीय
सहित विभागों की समीक्षा करने के
गठन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग
लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
मंजी दोहर 12.15 बजे ग्राम नैर्झड़
स्थित नवसेवा बीज प्रवेशक
मेजर कार्प उत्पादन एवं पतुंकरण कार्य
का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोहर



1 बजे सर्किट हाउस, बीजापुर विश्राम करेंगे। प्रवास के दूसरे दिन 3
पहुँचेंगे। दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट जुलाई को सुबह 9.30 बजे स्थानीय
सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक जनप्रतिनिधियों से भेंट कर क्षेत्रीय
में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा विकास कार्य पर चर्चा करेंगे।

जिलों के आदिम जाति विकास, कृषि, किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन एवं पशुधन विकास विभागों की योजनाओं और प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक के	इसके बाद सुबह 11 बजे स्थानीय आदिवासी छात्रावास एवं आश्रम का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 1.30 बजे वे बीजापुर से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे।
--	---

संक्षिप्त समाचार

सीएमओएआई एसईसीएल शाखा के
नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ
ग्रहण समारोह आयोजित



विलासपुर। एसईसीएल के वसंत विहार स्थित वसंत क्लब में आज, दिनांक 27 जून 2026 को कोल माइन्स ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमओआई) की एसईसीएल शाखा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि एसईसीएल के निदेशक (मानव संसाधन) श्री बिरंची दास रहे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नई कार्यकारिणी अधिकारियों के हितों के संरक्षण के साथ-साथ संगठन और कंपनी की प्रगति में सकारात्मक एवं रचनात्मक भूमिका निभाएंगी। इस अवसर पर सीएमओआई एसईसीएल शाखा के अध्यक्ष श्री आशीष त्यागी, उपाध्यक्ष श्री तिलकराज एवं श्री अजय पंडित, महासचिव श्री आलोक खुल्लर, संयुक्त महासचिव डॉ. अनु नेहा एवं डॉ. सुमित कृष्ण, कोषाध्यक्ष श्री अनुर रहठे तथा संयुक्त कोषाध्यक्ष श्री अजय गुप्ता ने अपने-अपने पदों की शपथ ग्रहण की। उल्लेखनीय है कि सीएमओआई एसईसीएल शाखा के चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत 6 जून 2026 को एसईसीएल मुख्यालय तथा 7 जून 2026 को विभिन्न क्षेत्रीय इकायों में मतदान संपन्न हुआ था। इसके उपरांत 8 जून 2026 को चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे। शपथ ग्रहण समारोह में एसईसीएल के अधिकारीगण एवं सीएमओआई के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष का बड़ा बयान, फ़र्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी के मामले में पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी, अगर कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेस करेगी प्रदर्शन

खिलासपुर। कुछ दिनों पूर्व लखनपुर विकासखंड के ग्राम चाँदों में आदिवासी मस्त राम मझवार के 3 एकड़ जमीन के फर्जी तरीके से रजिस्ट्री मामले में लखनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमिटी अध्यक्ष अमित सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है जहाँ उन्होंने कांग्रेस अमित सिंहदेव ने साफ़तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी पौडित पथ के साथ है तथा हर संभव प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा पौडित के लिए किया जाएगा। सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है लगातार शासकीय जमीन अधिग्रहण, फर्जी खुरीद बिक्री सहित जमीन संबंधी कई मामले मीडिया के माध्यम से लगातार सामने आ रहे हैं राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल पूछने पर सिंहदेव ने कहा की अगर इन मामलों में राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका है तो उन्हें तुरंत बदला जाना चाहिए या फिर उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। ब्लॉक अध्यक्ष ने अपने प्रतिक्रिया में यह बात भी सुनिश्चित की अगर चांदो ग्राम के पौडित व्यक्ति के मामले में कलेक्टर सरगुजा या पुलिस प्रशासन कोई पहल नहीं करते हैं तो ब्लॉक कांग्रेस कमिटी और जिला कांग्रेस कमिटी मिलकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगी और पौडित को न्याय नहीं मिल जाने तक अपना उग्र प्रदर्शन जारी रखेगी।

45 वर्षीय व्यक्ति की संदेहास्पद तरीके से इलाज के दौरान हुई मृत्यु

■ अंतिम संस्कार के समय शरीर में चोट और मारपीट की जानकारी के बाद मामला पहुंचा पुलिस थाने

■ मारपीट से मौत की जताई जा रही आशंका

सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम रिरकेला ठेपापारा से एक 45 वर्षीय व्यक्ति को संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु होने की बात निकलकर सामने आई है जहाँ अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बिना पोस्टमार्टम को ग्रह ग्राम लाया गया जहाँ अंतिम संस्कार के दौरान शरीर में चोट के निशान दिखने और मारपीट की जानकारी होने पुलिस चौकी पहुँचे और घटना की जानकारी दी वहीं पुलिस के द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया गया है वहीं मामले में

सूचनाकर्ता व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीत की आशंका जतायी गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुरा मामला लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम तिरकेला के ठेपापारा का है जहाँ एक 45 वर्षीय व्यक्ति कामेश्वर मझवार पिता बंधु मझवार की तबियत ज्यादा खराब होने पर उसे पहले लखनपुर इलाज के लिए लाया गया था जिसके बाद स्थिति गंभीर होने के कारण उसे चिकित्सकों के द्वारा अंबिकापुर रेफर कर दिया गया था जहाँ 27 जून को करीब 04 बजे व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई। जिसके बाद पूरे मामले की जांचकरी कुश्नी चौकी में दर्ज करायी गई जिसके बाद सारा मामला अब लखनपुर पुलिस के हाथों में है तथा लखनपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर व्यक्ति की संदेहास्पद मृत्यु के बाद कुछ विश्वसनीय सूत्रों की माने तो कुछ दिनों पहले मृतक का शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर अशान्ति भी हाई के साथ विवाद हुआ था जिसमें दोनों के बीच लड़ाई में मृतक को अंदरूनी चोटें आई थी जिसके बाद व्यक्ति



को इलाज के लिए लखनपुर लाया गया था जहाँ डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए मृतक को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया था जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अब

मामले में सच्चाई क्या है यह तो पुलिस की जाँच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। फ़िलहाल पुलिस द्वारा मामले में मर्ग कायम कर मामले की तफ़तीश की जा रही है।

खनिज विभाग कोरबा ने
सघन अभियान चला 14
जगह मारा छापा

कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश तथा उच्च संचालक, खनि प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले में अवैध उत्खनन पर पकड़ व भण्डारण पर प्रतिबंध लगाने के लिए शनिवार को विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत गठित चार खनि जांच दलों ने जिले के संदिग्ध स्थानों सीतामुढी, बरमपुर, कपाटमुड़ा, धरसिसिंगार, कुचना मोड़, बरबसपुर, कटंबटला, भैसामुड़ा, राहडी, मुनगडी, आमाखोखा, कसानिया, लखपुर, धवईपुर से रहित अन्य स्थानों पर छापामारक समन जांच की। जिस दौरान बरमपुर तथा पाली में रेत का अवैध परिवहन कर रहे एक टीपर और एक ट्रैक्टर पर कार्यवाही कराते हुए जप्त कर रहेदीबाजार थाना तथा पाली थाना की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ रखा गया है।

बालको की वजह से क्षेत्र का संपूर्ण विकास संभव लखन लाल देवांगन

कोरबा। भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) द्वारा सिविलिक सेंटर स्थित नवीनीकृत जुबली पार्क का लोकार्पण छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी) एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने किया। उद्घाटन समारोह में कोरबा नगर निगम की महापौर संजू देवी राजपूत, बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रौद्योगिक निदेशक राजेश कुमार सिंह, वार्ड 43 पार्षद हितानंद अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक, बालको के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। 'बालको की यह विस्तार यात्रा पूरे क्षेत्र के लिए एक आदर्श स्थापित करेगा।
